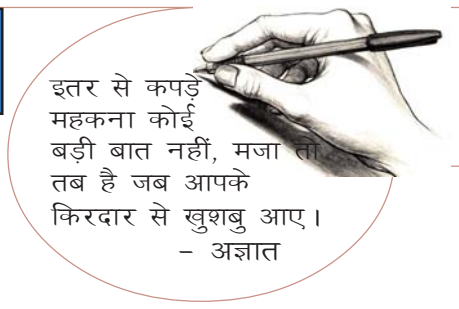

मत खोलें यह पिटारा

अभी तक यह कसरत केवल एक राज्य असम में ही की जा सकी है और इसके नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी में ही एक राय नहीं है। असम की बीजेपी सरकार में मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एनआरसी की सूची को रद्द करने की मांग की है।

अमित वर्मा

केंद्र सरकार को असम से सबक लेते हुए देश भर में एनआरसी लागू करने के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहीं यह भानुमती का पिटारा खोलने जैसा न हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में ऐलान किया था कि नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप की व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी। यानी कुछेक दस्तावेजों के आधार पर अपनी नागरिकता प्रमाणित करने वाले लोग ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। अभी तक यह कसरत केवल एक राज्य असम में ही की जा सकी है और इसके नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी में ही एक राय नहीं है। असम की बीजेपी सरकार में मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एनआरसी की सूची को रद्द करने की मांग की है।

सरमा ने यह भी कहा है कि अगर इसे पूरे देश में लागू करना है तो सभी राज्यों में एक ही कट ऑफ सूची होनी चाहिए। यानी असम के लिए कट ऑफ वाला साल 1971 है तो इसे ही सभी राज्यों पर लागू किया जाए। असम में चली लंबी तकलीफदेह प्रक्रिया के बाद एनआरसी की जो लिस्ट आई है, उससे शायद ही कोई संतुष्ट दिखा हो। 19 लाख लोग इससे बाहर हैं जिनमें देश के एक पूर्व राष्ट्रपति के परिजन भी शामिल हैं। अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों की इससे कोई पहचान नहीं हो पाई, जो कि इसका मकसद था। कई जेनुइन लोगों के बाहर रह जाने की बात सारी पार्टियां कह रही हैं। इसे लेकर भारी अफरातफरी मची और कुछ लोगों ने आत्महत्या तक का रास्ता अपना लिया। सोचा जा सकता है कि यही कवायद पूरे देश में दोहराने पर क्या होगा?

निवास प्रमाणपत्र जुटाना वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट बनाने जैसा नहीं है। असम में लोगों से 24 मार्च 1971 से पहले जारी कोई ऐसा दस्तावेज मांगा गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि इस तारीख से पहले वे या उनके पूर्वज यहां रहते थे। फिर किसी अन्य दस्तावेज से उन्हें इन पूर्वजों से अपना संबंध साबित करना था। देश भर में ऐसे कागजात जुटाने और जांचने के लिए जो रेलमपेल मचेगी उससे रोजमर्रा का काम बुरी तरह प्रभावित होगा। असम में इस पर करीब 1300 करोड़ खर्च हुए तो सोचा जा सकता है कि पूरे देश के लिए कितनी रकम चाहिए होगी। और इतना कुछ करने के बाद भी इसका मकसद पूरा होगा, इसकी क्या गारंटी है? इस प्रक्रिया ने जब एक राज्य में 19 लाख असंतुष्ट खड़े कर दिए तो पूरे देश में क्या होगा? अगर ऐसे करोड़ों लोग निकल आए तो उनका क्या किया जाएगा?

असम में तो एक ऐतिहासिक उलझन थी, जिसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता सुझाया था, लेकिन बाकी राज्यों में विदेशी घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। कोई राज्य अगर इससे इनकार कर दे तो क्या उसे इसके लिए बाध्य किया जा सकता है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो कह ही दिया है कि वह अपने यहां एनआरसी नहीं लागू करेंगी। कुल मिलाकर यह देश को एक व्यर्थ की परेशानी में झोंकने जैसा होगा। बेहतर होगा कि सरकार इस पर देश में आम सहमति बनाने के बाद ही आगे बढ़े।

सही राह पर

राबिन शर्मा

धर्म-दर्शन

अतीत की गलतियों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करना आसान है। अक्सर हम उन रिश्तों का विश्लेषण करते रहते हैं जो किसी कारणवश सफल नहीं पाये। कभी हम अपनी की हुई गलतियों की समीक्षा करते लगते हैं तो कभी उन व्यावसायिक फैसलों के बारे में सोचने लगते हैं जिससे लाभ मिल सकता था। हम लगातार इस अफसोस में अपना समय गुजारते हैं कि काश मैंने सही फैसला लिया होता। लेकिन एक बार के लिए आप इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दें। खुद के प्रति इतना कठोर ना बनें। आप एक मनुष्य हैं और मानवों को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो गलतियां करता रहता है। जब तक आप वही गलतियां फिर से नहीं दुहरा रहे और अतीत की गलतियों से सबक लेकर सही फैसला ले रहे हैं, तब तक आप सही राह पर हैं। उन गलतियों को स्वीकार कर आप जीवन में आगे बढ़ें।

संपादकीय

सड़क और सुरक्षा

यमुना एक्सप्रेस–वे पर हुए भीषण बस हादसे में 29 लोगों की मौत अत्यंत दुखदायी है। यूपी रोडवेज की एक डबल डेकर बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीती रात में वह सड़क छोड़कर 40 फीट गहरे नाले में जा गिरी। शुरुआती जांच में पता चला है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेस–वे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

वर्ष 2019 के पहले छह महीनों में ही यहां हुई 247 सड़क दुर्घटनाओं में 127 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2018 में 659 सड़क दुर्घटनाओं में 110 लोगों की जान गई थी। हर दुर्घटना को राज्य सरकार दुर्भाग्यपूर्ण बताती है, उस पर दुख व्यक्त करती है, मुआवजे का ऐलान भी करती है लेकिन एक्सीडेंट रोकने के गंभीर उपाय अब तक नहीं किए जा सके हैं। सोमवार के हादसे पर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इसके लिए वह जिम्मेवार नहीं है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस हाईवे का निर्माण यूपी सरकार ने करवाया है और इसका नियंत्रण नोएडा प्राधिकरण के पास है। जो भी हो, सवाल यह है कि इस तेज रफ्तार सड़क पर लोगों की जिंदगी कब तक इतनी सस्ती बनी रहेगी? सचाई यह है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सड़क परिवहन भारी अराजकता का शिकार है। कुछ राज्यों में तो स्थिति बेहद खराब है। वहां नियम–कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश भर में बसों के रख–रखाव, उनके परिचालन, ड्राइवरों की योग्यता और अन्य मामलों में एक–समान मानक लागू करने की जरूरत है, तभी देश के नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगे।

भारत के छात्रों को बाहर जाने से रोकने और अधिक से अधिक विदेशी स्टूडेंट्स को यहां लाने के लिए हमें अच्छी खासी संख्या में विश्वस्तरीय संस्थान चाहिए।

पढ़ने आएं भारत

कीर्ति पाण्डे

वित्त वर्ष 2019–20 के बजट में शिक्षा को लेकर कुछ अहम ऐलान किए गए हैं। सरकार ने स्टडी इन इंडिया योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसका मकसद विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित करना है। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। अगर देश के संस्थानों की क्वॉलिटी बढ़ेगी तो देश से प्रतिभावान छात्रों का पलायन रुकेगा, देश में शोध को बढ़ावा मिलेगा और भारत को नॉलेज पावर बनाने का सपना पूरा होगा। हालांकि यह लक्ष्य बहुत आसान नहीं है।

अब तक भारत से ब्रेन ड्रेन रोकने में कोई खास सफलता नहीं मिली है। उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अब जाकर देश के तीन उच्च शिक्षा संस्थान दुनिया के 200 प्रमुख संस्थानों में शुमार हो पाए हैं। भारत के छात्रों को बाहर जाने से रोकने और अधिक से अधिक विदेशी स्टूडेंट्स को यहां लाने के लिए हमें अच्छी खासी संख्या में विश्वस्तरीय संस्थान चाहिए। अभी आलम यह है कि देश में सुविधाएं बढ़ने के बाद भी विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है जबकि

बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटी है।

यूनेस्को के मुताबिक 2013 तक विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या एक लाख 42 हजार थी। 2010 से 2017 के बीच सिर्फ अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। एक जनवरी 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि भारत ने 2017 में 36,887 स्टूडेंट वीजा जारी किए, जबकि 2016 में 37, 947 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए थे। साफ है कि भारत में विदेशी छात्रों की रुचि घटी है। इस स्थिति को बदलना ही स्टडी इन इंडिया की चुनौती है।

संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में हम इनसे बहुत पीछे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग में होने वाले शोध में से एक तिहाई अमेरिका में होते हैं जबकि भारत से सिर्फ 3 फीसदी शोधपत्र प्रकाशित हो पाते हैं। उच्च शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा संस्थानों में उचित संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। अभी आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फीसदी शिक्षकों की कमी है। दिल्ली विश्वविद्यालय अस्थायी शिक्षकों के सहारे चल रहा है।

कई विश्वविद्यालयों में पिछले करीब 30 सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्वायत्तता एक जरूरी शर्त है, जबकि भारत में सरकारी और दूसरी तरह की दखलंदाजी बहुत ज्यादा है। संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए नियुक्ति एवं अन्य स्तरों पर विश्वस्तरीय प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा। सरकार अगर दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाए तो स्टडी इन इंडिया का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

सूडोकु नवताल-5175

सरल

2	9			5				4
4			2		7		8	
	1	6		8				3
8		5		9				7
3	6			2			1	9
1				3		5		2
5				7		6	3	
	3		1		8			5
9				6			2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5174 का हल

7	8	1	6	9	4	2	5	3
2	6	4	5	3	6	1	7	9
5	3	9	1	2	7	4	6	8
9	5	8	7	4	1	3	2	6
1	2	3	9	5	6	7	8	4
4	7	6	3	8	2	9	1	5
3	9	7	2	6	5	8	4	1
6	4	2	8	1	9	5	3	7
8	1	5	4	7	3	6	9	2

अपना ब्लॉग

फिरोज का विरोध करने वालो, काश!

गौरव। भारत केवल हिन्दुओं का देश नहीं है, यह मुस्लिम, इसाई और पारसियों का भी देश है। देश तभी विकास और शक्ति प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न समुदाय के लोग परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। यह मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि प्रकाश और जीवन का यह केन्द्र जो अस्तित्व में आ रहा है वह ऐसे छात्र प्रदान करेगा जो न सिर्फ बौद्धिक रूप से संसार के दूसरे श्रेष्ठ छात्रों के बराबर होंगे, बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, अपने देश से प्यार करेंगे और परम पिता के प्रति ईमानदार रहेंगे।' आपने ऊपर जो पढ़ा, यह वह संदेश है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू के छात्रों को दिया था। यह संदेश आज भी बीएचयू की ऑफिशल वेबसाइट के होमपेज पर सबसे ऊपर लगा हुआ दिख जाता है। लेकिन क्या बीएचयू के छात्रों ने इस संदेश को आत्मसात करने की कोशिश की? लेकिन क्या वाकई इस विषय पर विवाद होना चाहिए? क्या एक मुस्लिम प्रफेसर की संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में संस्कृत साहित्य विषय पढ़ाने के लिए की गई नियुक्ति का विरोध होना चाहिए?